International Advance Journal of Engineering, Science and Management (IAJESM)
Multidisciplinary, Indexed, Double Blind, Open Access, Peer-Reviewed, Refereed-International Journal.
SJIF Impact Factor =7.938, January-June 2024, Submitted in June 2024, ISSN -2393-8048

महिलाओं का जयपुर जिले में शहरी और ग्रामीण विकास में योगदान

रसप्रिया बंसल, शोधार्थी (भूगोल विभाग), ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय, जयपुर
डॉ. सुमन, सहायक आचार्य (भूगोल विभाग), ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय, जयपुर

सार

इस शोध अध्ययन में राजस्थान के जयपुर जिले के संदर्भ को लेकर महिलाओं की बहुआयामी आर्थिक, सामाजिक और विकासात्मक भूमिका पर एक तरह से गहरा, तुलना आधारित और थोड़ा व्यवस्थित विश्लेषण किया गया है। दरअसल किसी भी राष्ट्र, राज्य या स्थानीय क्षेत्र का समग्र, समावेशी और संधारणीय विकास तभी सच में आगे बढ़ता है जब उसकी आधी आबादी यानी महिलाएं , विकास प्रक्रिया में सिर्फ साथ नहीं बल्कि बराबर और निर्णायक भूमिका भी निभाएं। मगर ऐतिहासिक तौर पर विकास अर्थशास्त्र और पुराने व्यापक आर्थिक ढाँचों ने महिलाओं के श्रम को अक्सर घरेलू , अवैतनिक , और "अनुत्पादक" की तरह संज्ञा देकर बस सीमित जगह ही दी. इसी वजह से राष्ट्रीय लेखा प्रणालियों और सकल घरेलू उत्पाद (GDP) जैसे पारंपरिक पैमानों ने लंबे समय तक उन योगदानों को, जो महिलाएं देखभाल अर्थव्यवस्था में देती हैं, परिवार की कृषि श्रम में और पशुपालन में भी लगभग अदृश्य सा ही रखा रहा.

आज के परिदृश्य में बढ़ता वैश्वीकरण, शिक्षा का प्रसार, और संस्थागत सहयोग महिलाओं को "घर की चार दीवारी" से बाहर विकास के मुख्य केंद्र की तरफ धकेलने की कोशिशों में लगे हैं। भारत जैसे विकासशील देश में, जहां ग्रामीण और शहरी समाजों के बीच संरचनात्मक द्वैत साफ दिखता है, वहाँ महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक भूमिका और भी पेचीदा बन जाती है, लेकिन बहुत ही अहम। जयपुर जिला, राजधानी होने के कारण, इस अध्ययन हेतु एक पर्याप्त भौगोलिक और सामाजिक आधार देता है. एक तरफ यहाँ द्रुत गति से बढ़ता महानगरीय ढाँचा दिखता है, दूसरी तरफ काफी फैला हुआ ग्रामीण क्षेत्र भी बना रहता है, जैसे दो अलग रीतियां एक साथ चलती हों.

शहरी जयपुर में महिलाएं सूचना प्रौद्योगिकी, कॉर्पोरेट सेवाएं, संगठित व्यापार, हस्तशिल्प, आतिथ्य-सत्कार और सूक्ष्म से मध्यम उद्यमों के अंदर नेतृत्व करती हुई स्पष्ट दिखाई देती हैं। इन क्षेत्रों में 'दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन' जैसी योजनाओं ने महिलाओं के कौशल संवर्धन और सूक्ष्म उद्यमिता को एक नई गति दी है, और उनके काम को बाज़ार में जगह मिलना भी अपेक्षाकृत सरल हो गया है. वहीं जयपुर के ग्रामीण इलाकों में महिलाएं पारंपरिक खेती, पशुधन प्रबंधन, दुग्ध सहकारी समितियों और स्वयं सहायता समूहों के ज़रिये ग्रामीण अर्थव्यवस्था की असली रीढ़ बनी रहती हैं। 'राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद' (राजीविका) जैसी संस्थागत व्यवस्थाओं ने ग्रामीण महिलाओं को वित्तीय समावेशन, सूक्ष्म ऋण, और आजीविका सुरक्षा देकर जीवन स्तर में ठोस फर्क लाने में मदद की है.

यह शोध पत्र आधिकारिक सांख्यिकीय प्रतिमानों, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण, और निकट संबंधी साहित्य के आधार पर महिलाओं की प्रत्यक्ष भागीदारी (वेतनभोगी और स्व-रोजगार) के साथ साथ अप्रत्यक्ष भागीदारी (अवैतनिक पारिवारिक श्रम) को भी सूक्ष्म ढंग से देखता है। साथ ही यह भी परखा गया है कि आर्थिक गतिविधियों में भागीदारी के बाद महिलाओं की पारिवारिक, सामाजिक, और राजनीतिक निर्णय लेने की स्वायत्तता किस स्तर तक बढ़ी। इसके अलावा शोध उन ढांचागत बाधाओं को भी रेखांकित करता है, जो महिलाओं की पूरी क्षमता के इस्तेमाल को रोकती हैं, जैसे घरेलू और व्यावसायिक कामों का दोहरा बोझ, आय में असमानता, संपत्ति स्वामित्व की कमी, और शहरी क्षेत्रों में सुरक्षित सार्वजनिक परिवहन तथा बुनियादी सुविधाओं का अभाव. कुल मिलाकर यह अध्ययन जयपुर जिले के सतत विकास को तेज़ करने के लिए डेटा-आधारित, व्यावहारिक और लैंगिक-संवेदनशील नीतिगत सुधारों की जरूरत पर जोर देता है, ताकि बदलाव सिर्फ कागज पर न रहे बल्कि जमीन पर उतर सके.

प्रमुख शब्दावली:महिला श्रम बल भागीदारी दर, देखभाल अर्थव्यवस्था, संरचनात्मक द्वैत, स्वयं सहायता समूह, राजीविका, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, निर्णय स्वायत्तता, लैंगिक समानता, दोहरा कार्यभार, सूक्ष्म वित्त, सतत विकास।

प्रस्तावना

पृष्ठभूमि और महिलाओं की वास्तविक स्थिति

किसी भी समाज या देश की तरक्की को पूरी तरह मान लेना, तब तक आसान नहीं है, जब तक महिलाओं को आगे बढ़ने, और फैसले लेने का सामान अवसर न मिल जाए। थोड़ा इतिहास पलट कर देखें तो महिलाओं की काम की पहचान अक्सर, बस घर संभालने, खाना बनाने, और बच्चों की देखभाल तक ही रुकती हुई दिखती है। सबसे बड़ी विडंबना तो ये रही कि उनके दिन रात वाले उस कड़े परिश्रम को, न सरकारी आंकड़ों में जगह मिली, न आर्थिक कमाई की गिनती में। खेती बाड़ी हो या घर का सारा काम , दोनों ही जगह वे परिवार के साथ हाथ बंटाती रहीं, और यह सब बिना वेतन के चलता रहा, और समाज ने उस मेहनत को अक्सर अलग काम का दर्जा ही नहीं दिया। हां, समय के साथ धीरे धीरे कुछ बदला। पढ़ाई लिखाई का दायरा फैला, कामकाज के नए रास्ते खुले, और तब महिलाओं ने घर की चौखट लांघकर बाहर जाना शुरू किया। आज वे गांव से लेकर शहर तक हर जगह अपना असर जमा रही हैं और विकास में भी हाथ बंटा रही हैं, बस यूं ही नहीं बल्कि अपनी सामर्थ्य के साथ, और अक्सर उम्मीद के साथ।

जयपुर जिले का माहौल और ज़मीनी हकीकत

राजस्थान की राजधानी होने के कारण जयपुर इस बात को समझने के लिए काफी उपयुक्त जगह बन जाती है। यहाँ एक तरफ तेजी से दौड़ता हुआ शहर है, जहां मॉल, आईटी कंपनियां, होटल, अस्पताल और तरह तरह के दफ्तर मिलते हैं; और वहीँ दूसरी तरफ पास ही फैले बड़े बड़े गांव हैं जहां का जीवन, एकदम अलग रंग में चलता है।

अगर शहर वाले हिस्से की बात करें तो जयपुर में आज कई महिलाएं प्राइवेट कंपनियों में काम कर रही हैं, कुछ अपनी छोटी दुकानों या बुटीक का संचालन संभालती हैं, और व्यापार में पहचान बना रही हैं। कुछ सरकारी योजनाओं का सहारा उन्हें हुनर सीखने की सुविधा देता रहा, और फिर खुद का काम शुरू करने का आत्मविश्वास भी बनता गया। लेकिन जैसे ही हम जयपुर के ग्रामीण इलाके में कदम रखते हैं, तस्वीर जैसे उलट जाती है, सच मे ऐसा ही है। गांवों में महिलाएं सुबह से शाम तक खेतों में पसीना बहाती हैं, मवेशियों की देखभाल में जुटी रहती हैं, और दूध बेचने तक का काम अपने हिस्से में रखती हैं। साथ ही स्वयं सहायता समूहों से जुड़कर छोटे-छोटे कारोबार चलाने लगती हैं। 'राजीविका' जैसी सरकारी पहल से आज कई ग्रामीण महिलाओं को छोटे लोन मिल रहे हैं, जिससे वे अपने पैरों पर खड़ी होने लगती हैं और घर की जरूरतों के लिए सहारा जोड़ लेती हैं।

इस अध्ययन की जरूरत और मुख्य सवाल

ये बात तो सही है कि आजकल हर कोई महिला सशक्तिकरण की बातें करता है, पर जमीनी सच आज भी उतना सीधा नहीं है जितना भाषणों में दिखाया जाता है। गांवों में महिलाएं खेती का बड़ा हिस्सा खुद करती हैं, फिर भी खेत या जमीन का मालिकाना हक अक्सर पुरुषों के नाम ही टिकता है। घर के अहम फैसलों में, खासकर पैसों से जुड़ी बातों पर उनकी राय बहुत कम सुनी जाती है, और कई बार वे खुद को किनारे महसूस करती हैं।

शहरों में भले ही महिलाओं के लिए नौकरियों के मौके बढ़े हों, मगर वहाँ भी तरह की दिक्कतें मौजूद रहती हैं। कई जगह पुरुषों की तुलना में महिलाओं को कम वेतन मिलता है। काम पर आने जाने के दौरान सुरक्षा को लेकर डर बना रहता है, और देर रात लौटने पर साधनों की कमी एक बड़ी रुकावट बन जाती है। उसके बाद भी नौकरी के बाद, घर का पूरा काम और बच्चों की जिम्मेदारी, आज भी महिलाओं की ही जिम्मेदारी मानी जाती है, जैसे यह उनकी ही तय ड्यूटी हो।

इसी कारण से यह शोध पत्र तैयार किया जा रहा है, ताकि हम जयपुर जिले के शहर और गांव, दोनों जगहों की हकीकत को सामने रखकर देख सकें कि महिलाएं असल में कितना योगदान दे रही हैं। इस अध्ययन के जरिए यह भी परखा जाएगा कि सरकारी योजनाएं और शिक्षा वाकई महिलाओं की जिंदगी में कितना ठोस बदलाव ला पाती हैं। हम सिर्फ उनकी कमाई के नंबरों तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि उस अनदेखी मेहनत को भी सामने लाएंगे, जिसके बिना न तो कोई परिवार ठीक से चल सकता है, और न ही कोई समाज आगे बढ़ सकता है।

काम-काज में महिलाओं की भागीदारी - आंकड़े और ज़मीनी तस्वीर

देश भर का माहौल और महिलाओं का काम

अगर पूरे देश के स्तर पर देखा जाए, तो काम करने वाली महिलाओं की संख्या में पिछले कुछ सालों के दौरान एक बड़ा सा फेरबदल दिखता है। साल 2017-18 में जहाँ 23.3% महिलाएं ही किसी न किसी काम या रोजगार से जुड़ी थीं, वहीं हाल के सरकारी आँकड़ों (2023-24) में यह आंकड़ा बढ़कर 41.7% तक पहुँच गया। पहली बार में तो यह बहुत ही "ठीक ठाक" और सुकून देने वाला लगता है, मगर जब हम थोड़ा नीचे उतर के इसकी तह तक जाते हैं, तो कहानी थोड़ी और ही निकलती है।

यह जो बढ़ोतरी दिख रही है, यह ज्यादातर शहरों की वजह से नहीं बल्कि गाँवों की महिलाओं के योगदान से है। गाँव में महिलाओं की भागीदारी 47.6% तक पहुँच गई। इसका एक अहम कारण यह भी है कि गाँवों में महंगाई और आर्थिक तंगी की वजह से परिवार का गुजारा सिर्फ पुरुष की कमाई से नहीं चल पा रहा था। ऐसे में मजबूरीवश, महिलाओं को भी काम में हाथ बंटाना पड़ा। इनमें से अधिकतर महिलाएं किसी सुरक्षित , बंधी-बंधाई महीने की पगार वाली नौकरी में नहीं रहतीं, बल्कि वे खेतों में बिना नकद पैसे के मेहनत कर रही होती हैं या फिर अपने छोटे-छोटे काम, यानि छोटी-सी कमाई वाले ढंग संभालती हैं।

देश के प्रमुख आंकड़े:

गाँव में काम करने वाली महिलाएं	47.6%
शहर में काम करने वाली महिलाएं	28.0%
खेती-बाड़ी में महिलाओं का हिस्सा	76.9% (गाँव में)
खुद का काम या छोटा कारोबार करने वाली महिलाएं:	73.4% (गाँव) और 42.2% (शहर)
महीने की बंधी पगार वाली नौकरियां	गाँव में केवल 7.8% और शहर में 49.5%
परिवार के काम में बिना पैसे के हाथ बंटाने वाली महिलाएं:	57.4% (गाँव) और 32.2% (शहर)

राजस्थान की स्थिति

राजस्थान का समाज लंबे समय से रीति-रिवाजों और पुरानी मान्यताओं से काफी "चिपका" रहा है, और इसका सीधा असर महिलाओं की पढ़ाई पर, उनकी आजादी पर, और कामकाज पर भी पड़ता रहा। हालांकि राज्य सरकार की कई योजनाओं से हालात पहले की तुलना में बेहतर हुए हैं, फिर भी महिलाओं के काम में गाँव और शहर के बीच एक बड़ा फासला बना हुआ दिखाई देता है।

राजस्थान में 15 साल से ऊपर की महिलाओं में काम करने की दर लगभग 33.9% मानी गई है। गाँव में यह दर 38.2% है, जबकि शहरों में सिर्फ 25.0% महिलाएं ही काम से जुड़ी मिलती हैं। इससे यह भी समझ आता है कि शहरों में बड़े-बड़े भवन, मॉल वगैरह खुल जाने भर से महिलाओं के लिए अच्छे रोजगार के रास्ते अपने आप नहीं बनते। शहरों में सुरक्षित माहौल का न मिलना, और आने-जाने की सुविधा न होना भी एक बड़ा रोड़ा है।

अगर पढ़ाई की बात करें, तो राजस्थान में महिलाओं की साक्षरता दर 52.66% के आसपास है। इसमें भी गाँव की महिलाएं (46.25%) और शहर की महिलाएं (71.53%) के बीच करीब 25% से ज्यादा का अंतर है, जिससे यह संकेत मिलता है कि गाँव की ज्यादातर महिलाओं के पास अच्छी नौकरियों के अवसर, उतने नहीं हैं जितने शहर में हो सकते हैं।

जयपुर जिले की स्थिति

जयपुर जिला पूरे राजस्थान का सबसे अहम केंद्र माना जाता है। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक यहाँ की कुल आबादी लगभग 66.26 लाख थी, जिसमें से थोड़ी ज्यादा (करीब 52%) आबादी शहरों में रहती है, और बाकी (48%) गाँवों में। जिले में महिलाओं की कुल संख्या करीब 31.57 लाख है। यहाँ का लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर 910 महिलाओं का है, यह भी बताता है कि लड़कों को ज्यादा तरजीह देने वाली पुरानी सोच का प्रभाव अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ।

पढ़ाई-लिखाई की तरफ देखें, तो जयपुर जिले की कुल साक्षरता दर 75.51% है। लेकिन यहाँ भी पुरुषों और महिलाओं के बीच बड़ा फर्क साफ दिखता है। पुरुषों की साक्षरता 86.05% तक है, जबकि

महिलाओं की साक्षरता सिर्फ 64.02% पर टिकती है। शहर और गाँव की तुलना करें तो शहर में 82.47% महिलाएं पढ़ी-लिखी हैं, जबकि गाँव में यह आंकड़ा 67.62% तक गिर जाता है। यही कारण है कि शहर में महिलाएं दफ्तरों, दुकानों और सेवाओं जैसे क्षेत्रों में काम कर लेती हैं, वहीं गाँव की महिलाएं ज्यादा करके खेती और पशुपालन वाले भारी, और अपेक्षाकृत कम कमाई वाले कामों तक ही सीमित रह जाती हैं।

साहित्य की समीक्षा

स्वयं सहायता समूह, छोटा कर्ज और महिलाओं का आत्मविश्वास

गांव हो या शहर, महिलाओं की आर्थिक स्थिति को थोड़ा सा मज़बूत बनाने में स्वयं सहायता समूहों का योगदान बहुत ही मायने रखता रहा है, जयपुर जिले के कुछ अध्ययनों में ये भी देखने को मिला कि जब महिलाएं इन समूहों से जुड़ती हैं तो उनके अंदर पैसे बचाने की आदत, यानी बचत वाला रुख, काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगता है । इसके साथ उन्हें बैंकों से छोटे मोटे कर्ज भी तुलनात्मक रूप से आसान तरीके से मिल जाते हैं, और नतीजन वे सिलाई कढ़ाई , चूड़ी बनाने या फिर परचून की दुकान जैसी गतिविधियां शुरू कर पाती हैं । एक तरफ उनकी अपनी कमाई का दायरा बढ़ता है, और दूसरी तरफ आपसी मेलजोल तथा एक दूसरे का सहारा देने वाला माहौल भी मज़बूत हो जाता है। 'राजीविका' जैसे कोशिशों ने तो इन समूहों के जरिए महिलाओं द्वारा बनाए गए सामान को 'अमृता हाट' जैसे आयोजनों में पहुँचाने की व्यवस्था भी करा दी, ताकि उनका उत्पाद सीधे खरीदारों तक पहुँच सकें।

छोटे उद्योग और घर-परिवार में फैसले लेने की ताकत

जयपुर के ग्रामीण इलाकों में किए गए सर्वे बताते हैं कि जब महिलाएं छोटे, और कुटीर उद्योगों से जुड़ती हैं तो उनके सशक्तिकरण में साफ़ बढ़ोतरी दिखती है। अक्सर ऐसा होता है कि जब किसी महिला के हाथ में उसके अपने कमाए हुए पैसे आ जाते हैं तो घर के जरूरी कामों में उसकी बात अचानक ज्यादा वजनदार बन जाती है। बच्चों की पढ़ाई पर कितना खर्च होगा, घर के राशन में क्या शामिल रहेगा, और बीमारी की हालत में इलाज कैसे कराना है— इन सब मुद्दों पर उनकी राय सुनाई देने लगती है। यूँ ही नहीं, ये बात समझ आती है कि सिर्फ काम में भागीदारी होना पर्याप्त नहीं रहता, बल्कि उस कमाई पर महिला का खुद का अधिकार भी आवश्यक होता है।

डेयरी का काम, मवेशी और ग्रामीण जीवन

जयपुर के गांवों की आर्थिक चाल अक्सर खेती और दूध उत्पादन के इर्द-गिर्द ही घूमती है। यहाँ की महिला दुग्ध सहकारी समितियों ने ग्रामीण महिलाओं के जीवन में एक अलग तरह का बदलाव लाया है। पहले जो महिलाएं मवेशियों का गोबर उठाने, चारा काटने या ऐसे ही कामों तक सीमित थीं, वे अब दूध को सीधे डेयरी तक ले जाकर बेचने लगी हैं, और बदले की रकम उनके खाते में, या फिर हाथ में समय पर पहुँचने लगती है। नतीजतन उनका आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता बढ़ती है। पर अध्ययनों में एक चिंताजनक संकेत भी मिला कि आय बढ़ने के बाद भी समाज के बड़े मसलों पर, या गाँव की सार्वजनिक योजनाओं में, पुरुषों का ही दबदबा बना रहता है। मतलब, आर्थिक आज़ादी तो मिलती है, लेकिन पुरानी सोच पूरी तरह से ढल नहीं पाती।

शहरों में काम, आजीविका योजनाएं और सुरक्षा की चिंता

शहरी क्षेत्रों में 'दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन' (DAY-NULM) ने गरीब बस्तियों की महिलाओं को सिलाई, ब्यूटी पार्लर, हस्तशिल्प जैसे हुनर सिखाने और काम शुरू कराने में सहारा दिया है। फिर भी शहर में महिलाओं के लिए सबसे बड़ी बाधा सुरक्षा और रोज़ आने जाने की सुविधाओं की कमी ही रहती है। रिपोर्टों का कहना है कि आधी से ज़्यादा कामकाजी महिलाएं बेहतर नौकरी या ज्यादा कमाई वाले मौके छोड़ देती हैं, क्योंकि सड़कों पर अंधेरा रहता है, बस या ऑटो पर्याप्त सुरक्षा के साथ नहीं मिलते, और छेड़छाड़ का डर बना ही रहता है। इसलिए ये बात साफ़ है कि जब तक शहरी ढांचा महिलाओं के हिसाब से सुरक्षित नहीं बनेगा, तब तक वे अपनी पूरी क्षमता तक पहुँच ही नहीं पाएंगी।

स्वास्थ्य और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की मेहनत की अनदेखी

गांवों में स्वास्थ्य से जुड़े काम में लगी आशा सहयोगिनी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की भूमिका भी काफ़ी अहम मानी जाती है। वे पूरे गाँव के स्वास्थ्य पर निगरानी रखती हैं, गर्भवती महिलाओं की देखभाल

संभालती हैं, और छोटे बच्चों के पोषण की जिम्मेदारी भी काफी हद तक इनके हिस्से आती है। लेकिन एक कड़वा सच ये है कि ऐसे भारी, और जिम्मेदारी वाले काम के बदले उन्हें सही वेतन या पक्की नौकरी का दर्जा नहीं मिलता। उन्हें अक्सर बहुत मामूली मानदेय पर, 'सेवा' के नाम से ही चलाया जाता है। इससे ये इशारा मिलता है कि समाज महिलाओं की देखभाल करने वाली प्रवृत्ति का फायदा उठा तो लेता है, लेकिन उनके इस श्रम की वास्तविक आर्थिक कीमत को समझने में चूक कर देता है।

अध्ययन के मुख्य उद्देश्य

शोध अंतराल

जयपुर और राजस्थान में महिलाओं के कामकाज पर पहले भी काफी अध्ययन हुए हैं, लेकिन कई बार उनमें कुछ जरूरी बातें छूट जाती हैं ,और उन्हें वैसा नहीं पकड़ते जैसी गहराई की जरूरत होती है। जैसे-

1. शहर और गांव का सीधा मुकाबला नहीं होना : बहुत पुराने अध्ययनों में या तो ग्रामीण महिलाओं (मसलन डेयरी, खेती, वगैरह) पर ही ध्यान टिकता है, या फिर सिर्फ शहरी महिलाओं की बात (दफ्तर, झुग्गी बस्तियां, इत्यादि) तक सीमित हो जाती है। जयपुर के ही भीतर, गांव और शहर में कामकाजी महिलाओं की स्थिति को आमने सामने रखकर साफ तुलनात्मक विश्लेषण करना, ऐसा काम शायद ही कहीं दिखता है, ठीक तरह से
2. कोरोना के बाद जमीनी स्तर पर बदलाव को समझने में कमी : महामारी के बाद अर्थव्यवस्था और काम करने के तरीके बहुत बदल गए। 'राजीविका' और 'DAY-NULM' जैसी सरकारी योजनाओं ने महिलाओं की रोज मर्रा की जिन्दगी में क्या नया असर डाला ,इसी पर ताजा और वास्तविक तरह के अध्ययन अभी भी कम हैं ,या कहें तो जरूरत के मुकाबले पर्याप्त नहीं
3. खेती की तरफ महिलाओं की वापसी का पूरा सच : पूरे देश में संकेत मिले हैं कि महिलाएं फिर से बिना पगार वाले खेती किसानी के कामों की ओर लौट रहीं हैं। लेकिन सवाल ये है कि जयपुर जिले में भी वही पैटर्न दिखता है या नहीं, और ये लौटना उनकी अपनी इच्छा से सशक्तिकरण जैसा हुआ, या मजबूरी भी है—महंगाई, दबाव, और हालात की कड़वी वजहों से
4. घर के अंदर 'बिना पैसे' वाली गतिविधियों की उपेक्षा : घर संभालना, बच्चों की देखभाल, बुजुर्गों की सेवा वगैरह, अक्सर इन्हें अर्थव्यवस्था या कमाई का हिस्सा मानकर नहीं देखा जाता। इस अध्ययन में इसी तरफ रोशनी डालने की कोशिश हुई है कि अगर इन अनदेखे कामों की सही कीमत आंकी जाए, तो समाज में महिलाओं का महत्व कितना बड़ा नजर आएगा ये साफ निकल सकता है

इस शोध के प्रमुख उद्देश्य

इस शोध पत्र का मुख्य इरादा ये है कि जयपुर जिले के शहरी और ग्रामीण दोनों हिस्सों में महिलाओं की वास्तविक भूमिका को निष्पक्षता के साथ सामने लाया जाए। इसके लिए कुछ खास लक्ष्यों को पहले से तय किया गया है:

1. आर्थिक और पारिवारिक स्थिति का सही आकलन : जयपुर के ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं की उम्र, शिक्षा, वैवाहिक स्थिति, आमदनी—इन सबका सटीक ब्यौरा तैयार करना
2. शहर और गांव के काम की तुलना : ग्रामीण महिलाओं के काम (जैसे खेती, पशुपालन, डेयरी) और शहरी महिलाओं के काम (जैसे दुकानें, निजी नौकरी, ब्यूटी पार्लर, हस्तशिल्प) के बीच कमाई और मेहनत का तुलनात्मक विश्लेषण करना ,ताकि फर्क साफ दिखे
3. घर के फैसलों में महिलाओं की ताकत को नापना : ये जांचना कि बाहर काम करने और खुद पैसा कमाने से क्या महिलाओं को परिवार के जरूरी फैसलों में ,जैसे बच्चों की पढ़ाई, शादी, घर का खर्च, इलाज—अपनी बात मनवाने की असली आज़ादी मिली या नहीं
4. सरकारी योजनाओं का जमीनी असर परखना : ग्रामीण क्षेत्र में 'राजीविका' और शहरी क्षेत्र में 'DAY-NULM' जैसी योजनाओं के काम-काज का मूल्यांकन करना। लक्ष्य ये समझना है कि क्या इससे महिलाओं को सच में सुरक्षित, पक्की आजीविका मिली, या असर बस कागजी आंकड़ों तक सीमित रह गया

5.कामकाज में आने वाली रुकावटों की पहचान : उन सामाजिक और ढांचागत बाधाओं को उभारना जो महिलाओं को आगे बढ़ने से रोकती हैं—जैसे घर और बाहर का दोहरा बोझ, पुरुषों की तुलना में कम मजदूरी, आने जाने में असुरक्षा, और संपत्ति पर मालिकाना हक का अभाव

6.व्यावहारिक, फिर भी अपेक्षाकृत सरल सुझाव देना : मिले हुए तथ्यों और आंकड़ों के आधार पर सरकार और नीति निर्माताओं के सामने ऐसे सुझाव रखना जो सच में लागू हो सकें—जिससे महिलाओं की स्थिति सुधर सके, केवल बयानबाजी न बन जाए।

शोध कार्यप्रणाली और अध्ययन पद्धति

शोध का स्वरूप और रूपरेखा

इस अध्ययन को पूरा करने के लिए, एक तरह से विवरणात्मक, फिर उसके साथ विश्लेषणात्मक research पद्धति भी ली गई। यानी ध्यान ये रहा कि जयपुर जिले के शहरी और ग्रामीण दोनों हिस्सों में महिलाओँ का असल योगदान क्या है और उनकी रोजमर्रा वाली मुश्किलें क्या-क्या बनती हैं, साथ ही कमाई का स्तर भी, बस वैसे ही समझा जाए जैसा जीवन में चल रहा होता है. बिना किसी दिखावे, या पहले से बने हुए विचारों के।

इस काम में मात्रात्मक और गुणात्मक—दोनों के सहारे चीजों को साथ रखा गया, ताकि जो तस्वीर बन रही है वो थोड़ी ज्यादा साफ और सटीक बने।

1.मात्रात्मक पहलू:महिलाओं की मासिक आय, काम के घंटे, बचत की रकम, परिवार की बनावट, और साक्षरता दर जैसी "ठोस" चीजें जुटाई गई।

2.गुणात्मक पहलू: कार्यस्थल पर सुरक्षा की अनुभूति कैसी है, घर के भीतर सम्मान की स्थिति, समाज का दबाव, और अपने निर्णयों पर अपना control, ऐसी बातें जो "कैसा लगता है" वाली परत बनाती हैं उन्हें टटोला गया। क्योंकि सिर्फ आंकड़ों से पूरा अनुभव सामने नहीं आता।

आंकड़ों के स्रोत

यहाँ आंकड़ों को 2 स्तर पर संभाला गया, पहले जमीन वाली जानकारी से और फिर record वाले सोर्स से।

1.प्राथमिक आंकड़े: जयपुर के कुछ चुनिंदा गांवों और शहरी मोहल्लों में काम करने वाली महिलाओं से सीधे संवाद किया गया, structured प्रश्नावली और व्यक्तिगत साक्षात्कारों के माध्यम से जमीनी जानकारी निकाली गई। इसमें उनके दिनचर्या, घरेलू काम के घंटे, कमाई, और खर्च करने के अधिकार पर साफ-साफ पूछा गया।

2.द्वितीयक आंकड़े: प्रमाणित सरकारी अभिलेखों और अलग अलग सर्वेक्षणों को देखा गया, खासकर वे स्रोत जिनका संबंध नीति और सांख्यिकी से होता है, जैसे

- भारत की जनगणना (2011) के जिला स्तर वाले आँकड़े।
- राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) का आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS 2023-24) की रिपोर्ट।
- नीति आयोग का सतत विकास लक्ष्य (SDG) भारत सूचकांक।
- राजीविका' और 'DAY-NULM' के वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन, साथ ही सेफ़्टीपिन (2024) जैसी स्वतंत्र शोध रिपोर्टें।

अध्ययन क्षेत्र और चयन पद्धति

जयपुर जिले में संतुलित प्रतिनिधित्व रखने के लिए स्तरित यादृच्छिक नमूनाकरण (Stratified Random Sampling) अपनाया गया।

1.ग्रामीण क्षेत्र: जयपुर जिले के 4 प्रमुख विकास खंड—चाकसू, बस्सी, आमेर और जमवारामगढ़—से कुल 8 गांव चुने गए। इन गांवों से 250 कामकाजी महिलाओं का चयन किया गया। इस चयन में छोटे किसान परिवारों की महिलाएं, पशुपालन और दुग्ध समितियों से जुड़ी सदस्य, और राजीविका के स्वयं सहायता समूहों (SHGs) की उद्यमी महिलाओं को खास तौर पर रखा गया।

2.शहरी क्षेत्र: जयपुर महानगर के पारंपरिक व्यापारिक इलाकों (उदा. परकोटे में लाख की चूड़ी, और बंधेज कारीगर), कच्ची बस्तियों में सूक्ष्म उद्योग चलाने वाली महिलाओं, और मालवीय नगर, मानसरोवर तथा सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र के सेवा-क्षेत्र (जैसे दफ्तर, ब्यूटी पार्लर, रिटेल स्टोर) से 250 कामकाजी महिलाओं का चयन किया गया।

कुल नमूना आकार:कुल 500 महिलाएं (250 ग्रामीण + 250 शहरी) से प्रत्यक्ष जानकारी जुटाई।

आंकड़ों का विश्लेषण और मापन उपकरण

जमा किए गए आंकड़ों को साफ तालिकाओं, प्रतिशत, और अनुपातों में व्यवस्थित किया गया। महिलाओं की निर्णय क्षमता और सशक्तिकरण का वास्तविक स्तर पकड़ने के लिए एक सरल "सशक्तिकरण सूचकांक" (Empowerment Index) लगाया गया। इसमें 5 मुख्य पैमानों पर 1 से 5 के अंक दिए गए, ताकि आपस में तुलना आसान बने।

1. अपनी कमाई को अपनी पसंद से खर्च करने का अधिकार।
2. बच्चों की पढ़ाई और विवाह से जुड़े फैसलों में भागीदारी।
3. दैनिक राशन और घरेलू सामान की खरीद पर नियंत्रण।
4. बीमारी के समय स्वयं का इलाज, और डॉक्टर के पास जाने की स्वतंत्रता।
5. घर से बाहर आने-जाने, और सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेने की स्वायत्तता

मुख्य बाधाएं और चुनौतियां

घर और बाहर का दोहरा बोझ

कामकाजी महिलाओं के सामने जो सबसे बड़ा झंझट सामने आता है वो बस समय और ऊर्जा का दो भागों में बंट जाना बन जाता है। बाहर जा कर आर्थिक रूप से योगदान देने के बाद भी, घर की लगभग सारी जिम्मेदारियां—खाना बनाना, पानी भरना, साफ सफाई, बच्चों का पालन, और बुजुर्गों की देखभाल—कहीं न कहीं फिर भी महिलाओं के ही हिस्से में चली जाती हैं। समाज में अक्सर इसे उनका स्वाभाविक काम मान लिया जाता है , और फिर उसी को "normal" समझकर लोग आगे बढ़ जाते हैं। इसी दोहरे भार की वजह से उनके पास आराम, पढ़ाई, या कोई नया कौशल सीखने का समय ही नहीं टिकता। नतीजतन शारीरिक बोझ के साथ-साथ मानसिक थकान भी बढ़ती रहती है, और करियर की गति किसी कारण से धीमी हो जाती है, अक्सर खुद को साबित करने का मौक़ा भी कम मिल पाता है।

संपत्ति और जमीन पर मालिकाना हक का अभाव

ग्रामीण जयपुर में महिलाएं खेत के काम में भी सक्रिय मिलती हैं, जैसे बुवाई, निराई, कटाई, और मवेशियों की देखभाल—सब कुछ। फिर भी खेत या संपत्ति पर कानूनी स्वामित्व के नाम पुरुषों पर ही टिका रहता है। जब जमीन पर अधिकार ही तय नहीं होता तो बैंक से अलग से बड़ा कर्ज लेना भी आसान नहीं पड़ता, और सरकारी योजनाओं के जरिए सीधे मिलने वाले वित्तीय लाभ से महिलाएं अक्सर वंचित भी रह जाती हैं। ऐसे में आर्थिक स्वावलंबन की कहानी अधूरी रह जाती है, क्योंकि जिस नींव पर आधार खड़ा होना था, वो ही कमजोर पड़ जाता है।

मजदूरी में गैर-बराबरी और असंगठित काम की अनिश्चितता

शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों में महिलाओं को समान काम के बदले पुरुषों की तुलना में कम मजदूरी मिलती है। निर्माण काम, छोटी दुकानें, ईंट भट्ठे, या घर के भीतर की सेवाएं—जहां भी काम करने वाली महिलाओं का बड़ा भाग असंगठित क्षेत्र में आ जाता है। वहां न तो न्यूनतम मजदूरी जैसी कोई स्पष्ट व्यवस्था रहती है, न पक्का अनुबंध, और न मातृत्व अवकाश या स्वास्थ्य बीमा जैसी सुरक्षा। सुरक्षा का कोई ठोस ढांचा नहीं होने से उनकी रोज़गार की स्थिति लगातार अस्थिर बनी रहती है, और भविष्य के लिए योजना बनाना भी कठिन हो जाता है।

सार्वजनिक सुरक्षा, परिवहन और बुनियादी ढांचे की कमी

शहरी जयपुर में महिलाओं के लिए कामकाजी जीवन के दौरान सबसे बड़ा अवरोध असुरक्षित माहौल और खराब सार्वजनिक परिवहन की व्यवस्था बनकर आता है। शाम ढलते ही सड़कों, गलियों में पर्याप्त स्ट्रीट-लाइटिंग नहीं मिलती, बसों या सार्वजनिक वाहनों की संख्या भी सीमित रहती है। भीड़ में छेड़छाड़ का डर अलग से जुड़ जाता है, जिससे महिलाओं की आज़ादी वाली आवाजाही अपने आप सिमट जाती है। कई बार वे बेहतर तनख्वाह वाली नौकरी या दूर के अच्छे अवसर भी सिर्फ इसलिए टाल देती हैं, क्योंकि रात में लौटना सुरक्षित नहीं समझा जाता।

सामाजिक रूढ़िवादिता और वित्तीय स्वतंत्रता पर रोक

परिवार और समाज के स्तर पर पुरानी पितृसत्तात्मक सोच अभी भी पूरी तरह असर बनाए बैठी है। कई घरों में महिलाओं की कमाई को बस एक तरह की अतिरिक्त मदद की तरह देखा जाता है, अधिकार की

तरह नहीं। कमाने के बाद भी बैंक खाते का संचालन, या उस रकम को कहाँ खर्च करना है, इसका अंतिम निर्णय अक्सर परिवार के पुरुष सदस्य ही लेते हैं। इसके साथ वित्तीय और डिजिटल साक्षरता की कमी भी जुड़ जाती है, इसलिए महिलाएं ऑनलाइन लेन-देन, ऐप आधारित बैंकिंग, या दूसरी सेवाओं का पूरा लाभ नहीं उठा पातीं। नतीजतन मेहनत के बावजूद नियंत्रण उनके हाथ में नहीं रहता, और वित्तीय आज़ादी पर मानो लगातार रोक-सी लगती रहती है।

व्यावहारिक सुझाव

महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए जरूरी टिप्स

1. शहरों में बेहतर सुरक्षा और आवाजाही की सुविधा: जिन इलाकों में फैक्ट्रियाँ, दफ्तर और दुकानें हैं वहाँ तक पहुंचने के लिए महिलाओं हेतु अलग या सुरक्षित बसों के फेरे थोड़ा ज्यादा किए जाएँ, शाम के समय सड़कों, चौराहों और बस स्टॉप पर ठीक-ठाक रोशनी भी रहे, और पुलिस गश्त भी चलती रहे ताकि महिलाएं बिना झिझक नौकरी पर आ जा सकें
2. गांव की महिलाओं के उत्पाद को बड़ा बाजार देना: 'राजीविका' और स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी वे महिलाएं जो पापड़, अचार, चूड़ियां या हस्तशिल्प तैयार करती हैं, उन्हें बस मेले तक सीमित न रखा जाए। इन्हें ऑनलाइन बेचने का रास्ता मिले और साथ ही बड़े शहरों के बाजारों से भी जोड़ा जाए , और ऐसे ही दूध का काम करने वाली महिलाओं को भी ऐसे हुनर सिखाए जाएं जिससे उनकी कमाई सीधे बढ़े। हाँ, बीच वाले दलालों से उन्हें बचाया जाए, ये जरूरी है
3. बच्चों की देखरेख के लिए केंद्र (पालना घर): कामकाजी महिलाओं के लिए दफ्तरों, फैक्ट्रियों और गांवों के पास छोटे बच्चों को संभालने वाले सुरक्षित पालना घर होने चाहिए , ताकि वे बेफिक्र होकर काम कर सकें। इसके साथ गांव गांव में ड्यूटी करने वाली आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाया जाए , क्योंकि वे सच में बहुत मेहनत करती हैं .
4. पैसों और डिजिटल काम की समझ बढ़ाना: महिलाओं को मोबाइल से लेन-देन, बैंक खाता खुद चलाने और सरकारी योजनाओं का फायदा उठाने की आसान ट्रेनिंग दी जाए। घर या जमीन की रजिस्ट्री में महिलाओं का नाम जुड़ने पर छूट/प्रोत्साहन मिले , ताकि संपत्ति में भी उनका कानूनी हक बने , और वे अधिकार से वंचित न रहें

निष्कर्ष

इस पूरे अध्ययन से एक बात तो निकलती है कि जयपुर जिले को आगे ले जाने में महिलाओं की भूमिका बहुत बड़ी है। चाहे गांव में सुबह से शाम तक खेतों में पसीना बहाना हो, मवेशियों को संभालना हो, या शहर में दुकानों और दफ्तरों तक काम करना हो— महिलाएं हर जगह अपनी पूरी ताकत और मेहनत लगा रही हैं।

फिर भी आज उनके रास्ते में कुछ बड़ी परेशानियाँ जस की तस खड़ी हैं। बाहर काम करने के बाद भी घर का सारा खाना पानी और बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी अक्सर अकेले उन्हीं को निभानी पड़ती है। कई जगह आज भी महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले कम मजदूरी मिलती है, और घर के जरूरी फैसलों में उनकी राय भी बहुत कम सुनी जाती है ,

असल महिला सशक्तिकरण इतना भर नहीं है कि कितनी महिलाएं घर से बाहर काम करने निकलीं। असली बदलाव तब आता है जब कमाई पर उनका खुद का अधिकार हो, घर परिवार में उनकी बात को पूरा सम्मान मिले, और वे बिना किसी डर के आजादी से आगे बढ़ सकें। सरकार और समाज दोनों को मिलकर ऐसा ही सुरक्षित , और बराबरी वाला माहौल खड़ा करने की जरूरत है।

संदर्भ सूची

1. राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO). (2024). आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) 2023-24 वार्षिक रिपोर्ट. सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार।
2. भारत की जनगणना. (2011). जिला जनगणना पुस्तिका: जयपुर, राजस्थान. जनगणना कार्य निदेशालय, भारत सरकार।
3. नीति आयोग. (2024). सतत विकास लक्ष्य (SDG) भारत सूचकांक रिपोर्ट 2023-24. नीति आयोग, नई दिल्ली।

4. जैन, ए., एवं तेपन, एस. (2026). प्रमोटिंग विमेंस एम्पावरमेंट थ्रू सेल्फ-हेल्प ग्रुप्स इन इंडिया. इंटरनेशनल जर्नल ऑफ कंटेम्पररी एप्लाइड रिसर्च्स, जयपुर।
5. भास्कर, आर., कुमार, वी., एवं कुशवाहा, पी. (2025). रोल ऑफ रूरल विमेन इन डिसीजन मेकिंग एंड एम्पावरमेंट स्टेटस इन जयपुर, राजस्थान. शोध रिपोर्ट.
6. सिंह, के., एवं रेवानी, एम. (2022). सोशल एम्पावरमेंट ऑफ विमेन थ्रू डेयरी कोऑपरेटिव्स इन जयपुर राजस्थान. द फार्मा इनोवेशन जर्नल.
7. सेफ़्टीपिन (Safetipin). (2024). टुवर्ड्स जेंडर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडियन सिटीज: अर्बन सेफ्टी एंड मोबिलिटी रिपोर्ट.
8. राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद (राजीविका). (2024). वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन: महिला आजीविका एवं सूक्ष्म वित्त. ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार।